Samyak
An Institute For Civil Services

MODEL ANSWER

Q. The recent reimposition of the Protected Area Regime (PAR) in North Eastern states highlights ongoing security concerns in these areas. In the context of this development, discuss the unique security, socio-political, and economic challenges faced by the North Eastern region.

The Protected Area Regime (PAR), governed by the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, restricts foreign nationals from entering specific border areas in India without special permission. It was relaxed in 2010 for Manipur, Mizoram, and Nagaland to boost tourism. However, its recent reimposition highlights renewed security concerns in the region facing illegal immigration, ethnic conflicts, and instability due to its proximity to Myanmar.

Security Challenges in the North East

1. **Illegal Immigration**
    - Uncontrolled influx of immigrants from Myanmar, particularly the Chin community, linked to ethnic tensions among Kukis, Zomis, and Meiteis in Manipur. The porous Indo-Myanmar border facilitates unchecked cross-border movements, exacerbating demographic and security concerns.
2. **Insurgency and Ethnic Violence**
    - Active insurgent groups, such as NSCN-IM in Nagaland and valley-based groups in Manipur, challenge state authority.
    - Ethnic clashes, such as the Meitei-Kuki conflict, have led to loss of life and displacement of over 60,000 individuals.
3. **Free Movement Regime (FMR) and Border Challenges**
    - The erstwhile FMR allowing tribal communities to cross borders has been scrapped, creating discontent in Mizoram and Nagaland. Further, plans to fence the Indo-Myanmar border face logistical and political hurdles.
4. **Drug Trafficking and Organized Crime**
    - The region's proximity to the "Golden Triangle" has made it a hub for narcotics trade, further complicating law and order.

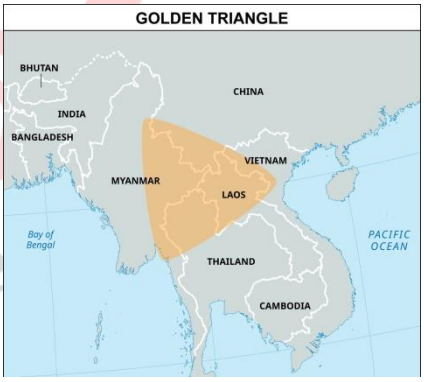

Socio-Political Challenges

1. **Ethnic Fragmentation and Identity Politics**
    - Deep divisions between communities, like Meiteis, Nagas, and Kukis, perpetuate violence and distrust. Further, the resistance to reimposition of PAR in Nagaland reflects the delicate balance between security measures and ethnic autonomy.
2. **Governance and Confidence Deficit**
    - Former police chiefs, like Prakash Singh, point to inadequate political initiatives and lack of trust-building efforts. Moreover, fragile governance mechanisms, combined with external influences, deepen instability.
3. **Impact of Policies like Citizenship Amendment Act (CAA)**
    - Fear of demographic dilution under the CAA has intensified existing insecurities, particularly in Assam and Manipur.

Economic Challenges

1. **Underdeveloped Infrastructure and Tourism**
    - Poor road and rail connectivity limit market access and economic integration with the rest of India Events like Nagaland's Hornbill Festival draw tourists but face limitations due to infrastructural and accessibility issues.

- Slow progress on key projects like the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway affects regional trade prospects.

2. **Agricultural and Industrial Underdevelopment**
    - Agriculture remains subsistence-oriented with limited market access and processing facilities. Cooperative failures, as seen in ginger cultivation in Assam, highlight market inefficiencies.
    - Initiatives like the North East Industrial Development Scheme (NEIDS) have had limited success in attracting investments.

The challenges of the North East are deeply interwoven with its unique geography, diverse population, and historical complexities. Addressing these requires a balanced approach of security enhancement, socio-political reconciliation, and economic empowerment. Integrating the North East into India's growth narrative will not only uplift the region but also strengthen the nation's strategic and economic position globally.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न: हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (पीएआर) को फिर से लागू किया जाना इन क्षेत्रों में जारी सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है। इस घटनाक्रम के संदर्भ में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामने आने वाली अनूठी सुरक्षा, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करें।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (पीएआर), जो विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 द्वारा शासित है, विदेशी नागरिकों को विशेष अनुमति के बिना भारत के विशिष्ट सीमा क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के लिए 2010 में इसमें ढील दी गई थी। हालाँकि, हाल ही में इसे फिर से लागू करने से म्यांमार से निकटता के कारण अवैध आप्रवास, जातीय संघर्ष और अस्थिरता का सामना करने वाले क्षेत्र में नए सिरे से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ सामने आई हैं।

उत्तर पूर्व में सुरक्षा चुनौतियाँ

1. **अवैध आप्रवास**
    a. म्यांमार से विशेष रूप से चिन समुदाय के आप्रवासियों का अनियंत्रित प्रवाह, मणिपुर में कुकी, ज़ोमिस और मैतेई के बीच जातीय तनाव से संबंधित है। भारत-म्यांमार की सीमा की प्रकृति अनियंत्रित सीमा पार आवागमन को सुविधाजनक बनाती है, जिससे जनसांख्यिकीय और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
2. **उग्रवाद और जातीय हिंसा**
    a. नागालैंड में NSCN-IM और मणिपुर में घाटी आधारित समूह जैसे सक्रिय उग्रवादी समूह राज्य प्राधिकरण को चुनौती देते हैं।
    b. मैतेई-कुकी संघर्ष जैसे जातीय संघर्षों के कारण 60,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोग विस्थापित हो गए हैं।
3. **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) और सीमा संबंधी चुनौतियाँ**
    a. आदिवासी समुदायों को सीमा पार करने की अनुमति देने वाली पूर्ववर्ती FMR को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मिज़ोरम और नागालैंड में असंतोष पैदा हो रहा है। इसके अलावा, भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना को राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
4. **मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध**
    a. "गोल्डन ट्राएंगल" से इस क्षेत्र की निकटता ने इसे मादक पदार्थों के व्यापार का केंद्र बना दिया है, जिससे कानून और व्यवस्था और भी जटिल हो गई है।

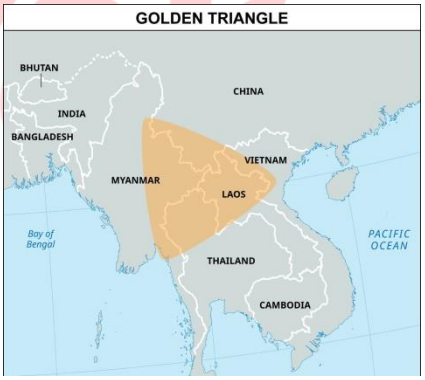

सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियाँ

1. **जातीय विखंडन और पहचान की राजनीति**
    a. मैतेई, नागा और कुकी जैसे समुदायों के बीच गहरे विभाजन ने हिंसा और अविश्वास को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, नागालैंड में पीएआर को फिर से लागू करने का प्रतिरोध सुरक्षा उपायों और जातीय स्वायत्तता के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है।
2. **शासन और विश्वास की कमी**
    a. प्रकाश सिंह जैसे पूर्व पुलिस प्रमुख अपर्याप्त राजनीतिक पहल और विश्वास-निर्माण प्रयासों की कमी की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा, बाहरी प्रभावों के साथ मिलकर नाजुक शासन तंत्र अस्थिरता को बढ़ाता है।
3. **नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसी नीतियों का प्रभाव**
    a. सीएए के तहत जनसांख्यिकीय कमजोर पड़ने के डर ने मौजूदा असुरक्षाओं को और बढ़ा दिया है, खासकर असम और मणिपुर में।

आर्थिक चुनौतियाँ

1. **अविकसित अवसंरचना और पर्यटन**

a. खराब सड़क और रेल संपर्क भारत के बाकी हिस्सों के साथ बाजार तक पहुँच और आर्थिक एकीकरण को सीमित करता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन अवसंरचना और पहुँच संबंधी मुद्दों के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
b. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर धीमी प्रगति क्षेत्रीय व्यापार संभावनाओं को प्रभावित करती है।

2. कृषि और औद्योगिक अविकसितता

a. कृषि की सीमित बाजार पहुँच और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ निर्वाह-उन्मुख बनी हुई है। सहकारी विफलताएँ, असम में अदरक की खेती के संदर्भ में देखा गया है। यह बाजार की अक्षमताओं को उजागर करती हैं।
b. उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना (NEIDS) जैसी पहलों को निवेश आकर्षित करने में सीमित सफलता मिली है।

पूर्वोत्तर की चुनौतियाँ इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति, विविध जनसंख्या और ऐतिहासिक जटिलताओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए सुरक्षा को बढ़ाने, सामाजिक-राजनीतिक सामंजस्य और आर्थिक सशक्तिकरण के संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा में शामिल करने से न केवल इस क्षेत्र का उत्थान होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की सामरिक और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

Samyak
An Institute For Civil Services